>

Title: Need to restore the original quota of PDS to Madhya Pradesh.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाला राशन का कोटा कम कर दिया गया है। जिसके कारण प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को बहुत असुविधा हो रही है। मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुलय प्रदेश है और केन्द्र सरकार द्वारा राशन का कोटा कम करने के कारण लोगों में भारी आक्रोश है।

अतः मेरा केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का खाद्यान्न का पूरा कोटा जारी करें ताकि आदिवासी क्षेत्रों मंडला, झाबुआ, धार, बड़वानी, बैतूल, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनुपर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, पन्ना छत्तरपुर, रतलाम और खंडवा आदि क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों कोपूरा राशान मिल सके।